डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 मार्च, 2024, डिस्पेच दिनांक 16 मार्च, 2024

| वर्ष 67 | अंक 20 | भोपाल | 16 मार्च, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

डेटाबेस से सहकारिता की हर एक जानकारी अब एक क्लिक पर मिलेगी : अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल का लोकार्पण और 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023: एक रिपोर्ट' का विमोचन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का स्वभाव है कि वो साहसिक फैसले लेते हैं और उन्हें अंजाम तक पहुंचाते हैं

डेटाबेस से सहकारिता क्षेत्र का विस्तार, डेवलपमेंट और डिलीवरी सुनिश्चित होगी

सहकारिता क्षेत्र के विकास को Compass की तरह दिशा दिखाएगा राष्ट्रीय डेटाबेस

देशभर में कहाँ सहकारी समितियां कम हैं, उस गैप की पहचान कर सहकारिता के विस्तार में मददगार साबित होगा राष्ट्रीय डेटाबेस

सहकारिता डेटाबेस पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और स्टेकहोल्डर्स के लिए अमूल्य संसाधन का काम करेगा

यह डेटाबेस भारत की पूरी सहकारिता गतिविधियों की जन्मकुंडली है, इसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाया गया है

डेटाबेस पोर्टल के माध्यम से छोटी सहकारी संस्थाएं अपने विस्तार के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगी

डेटाबेस में पैक्स से एपैक्स, गांव से शहर, मंडी से ग्लोबल मार्केट और स्टेट से अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस तक जोड़ने की पूरी संभावना मौजूद है

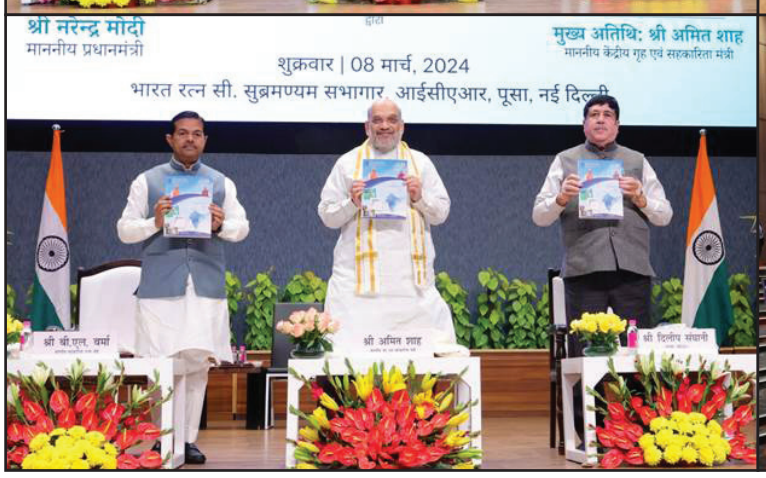

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण और 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023: एक रिपोर्ट' का विमोचन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री बी एल वर्मा और डॉ. आशीष कुमार भूटानी, सचिव, सहकारिता मंत्रालय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि आज सहकारिता क्षेत्र, इसके विस्तार और इसे मज़बूत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है जब 75 साल बाद पहली बार सहकारिता डेटाबेस का लोकार्पण हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज सहकारिता क्षेत्र के विस्तार और उसे गति प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हज़ारों लोगों के दो साल तक किए गए परिश्रम के बाद आज हमें ये सफलता मिली है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि 60 के दशक के बाद ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक राष्ट्रीय नीति के तहत हर राज्य के सहकारिता आंदोलन के बीच समन्वय हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने साहसिक फैसला लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाते हुए केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में देश के सभी Primary Agriculture Credit Society (PACS) कम्प्यूटराइज्ड हो गए हैं, उनके कारोबार में वृद्धि करने के लिए कॉमन बायलॉज़ सभी राज्यों ने स्वीकार किए हैं और आज सभी पैक्स विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने एडवाइज़री के स्वरूप में मॉडल बायलॉज़ बनाए जिनके तहत पैक्स बहुआयामी बने और कई काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी राज्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन मॉडल बायलॉज़ को स्वीकार किया है और इसी से पैक्स के विस्तार का रास्ता खुला है।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमने 20 नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ा है जिससे पैक्स मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से इनके विकास की कई संभावनाएं खुलीं और ये तय किया गया कि 2027 से पहले देश की हर पंचायत में एक पैक्स होगा। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय के बाद समस्या आई कि हमें ये पता नहीं था कि गैप कहां है और तब इस डेटाबेस का विचार आया, जिसके द्वारा गैप की पहचान कर विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेटाबेस सहकारिता क्षेत्र के विकास को Compass की तरह दिशा दिखाएगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के ग्रामीण अर्थतंत्र और जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने और पिछले 10 साल में देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों लोगों को देश के अर्थतंत्र और विकास के साथ जोड़ने का काम सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि इस कोऑपरेटिव डेटाबेस से सहकारिता का विस्तार, डिजिटल माध्यम से डेवलपमेंट और डेटाबेस से डिलिवरी का काम होगा। उन्होंने कहा कि डेटा, डेवलपमेंट को सही दिशा देने का काम करता है और गैप का एनालिसिस करने में ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस काल में हम एक नए ट्रेंड का अनुभव कर रहे हैं – डेटा गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस और एंटिसिपेटरी गवर्नेंस और इन तीनों के सामंजस्य से विकास का एक नया मॉडल खड़ा होता है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मोदी सरकार सहकारिता आंदोलन को जनआंदोलन के स्वरूप में बदलने का प्रयास कर रही है-अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NU-CFDC) का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकारी व्यवस्था के सहयोग से सहकारिता आंदोलन द्रुत गति से चलेगा और देश के अर्थतंत्र में अपना सम्मान हासिल करेगा

Cooperation among Cooperatives की भावना से मजबूत होगा सहकारिता आंदोलन

हर शहर में अर्बन कॉपरेटिव बैंक बनाने का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए - केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

अंब्रेला संगठन-NUCFDC के बनने के बाद देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का विकास कई गुना बढ़ जाएगा

NUCFDC, अर्बन कोआपरेटिव बैंकों की समस्याओं के निवारण का गेटवे है

आम जनता के जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं

NUCFDC छोटे बैंकों का सुरक्षा कवच है, जिससे डिपॉजिटर्स का विश्वास भी बढ़ेगा और आने वाले दिनों में काम में भी बढ़ोतरी होगी

NUCFDC सिर्फ बैंकों के संकट के समय ही नहीं, बल्कि उनके विकास, आधुनिकीकरण व क्षमता बढ़ाने का जरिया बनेगा

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सहकारिता राज्यमंत्री श्री बी एल वर्मा और डॉ. आशीष कुमार भूटानी, सचिव, सहकारिता मंत्रालय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि जब तक सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार और परस्पर आगे बढ़ाने की ताकत नहीं दी जाएगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि लगभग 20 साल के संघर्ष के बाद आज नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हो रही है और ये हम सबके लिए बहुत शुभ दिन है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि पहले सहकारिता मंत्रालय और सहकारिता क्षेत्र अनेक मंत्रालयों में बिखरा हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज़ादी के 75 वर्षों के बाद अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकारिता को एक नया जीवन दिया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को एक अंब्रेला, सहकारिता मंत्रालय के रूप में मिला है। श्री शाह ने कहा कि सवा सौ साल तक सहकारिता क्षेत्र जूझता रहा और अपने अस्तित्व को बचाता रहा, लेकिन अब सरकारी व्यवस्था के सहयोग से ये द्रुत गति से चलेगा और देश के अर्थतंत्र में अपना सम्मान हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को जनआंदोलन के स्वरूप में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में विकास का पैरामीटर सिर्फ आंकड़े नहीं हो सकते, बल्कि देश के विकास में कितने लोगों की सहभागिता है, ये बहुत बड़ा पैरामीटर होना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि ये अंब्रेला संगठन समय की ज़रूरत था और सेल्फ-रेगुलेशन के लिए एक प्रकार की नई शुरूआत है। उन्होंने कहा कि इस संगठन के बनने के बाद देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का विकास कई गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी विश्वसनीयता के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम खुद को अपग्रेड करें और भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में स्पर्धा में नहीं टिक सकेंगे। श्री शाह ने कहा कि अंब्रेला संगठन का एक प्रमुख काम बीआर एक्ट के लिए छोटे से छोटे बैंक को तैयार करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें हर शहर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खोलने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना चाहिए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव फाइनेंस में अच्छा काम करने वाली क्रेडिट सोसाइटी को बैंक में कन्वर्ट करने के लिए इस अंब्रेला संगठन को एक व्यवस्था करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि NUCFDC का एक उद्देश्य क्रेडिट सोसाइटीज और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की सेवाओं और संख्या में विस्तार करना भी होना चाहिए। हमें एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए कि हर शहर में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैसे बने। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए इसे प्रासंगिक भी बनाना होगा और उसका विस्तार भी करना होगा। उन्होंने कहा कि अंब्रेला संगठन से छोटे बैंकों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, बैंकों और रेगुलेटर के बीच संवाद का काम भी सुचारू संवाद का काम भी यह अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। उन्होंने कहा कि इस संगठन को हमारी सीमाओं को व्यापक और सर्वस्पर्शीय बनाने का काम करना है। उन्होंने कहा कि अगर हम कोऑपरेटिव का विस्तार करना चाहते हैं तो इसके लिए अंब्रेला संगठन को मजबूत करना अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का दायित्व है।

श्री अमित शाह ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को देशभर में व्यापार करने के लिए ज़रूरी सुविधाओं के लिए क्लीयरिंग की भी एक व्यवस्था बनानी होगी। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास 1500 बैंकों की 11000 शाखाओं और 5 लाख करोड़ रूपए के डिपॉजिट और 3.50 लाख करोड़ के ऋण की कलेक्टिव स्ट्रैंथ है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी ताकत है और हमें न सिर्फ इसे बढ़ाने का लक्ष्य रखना है बल्कि इसे संयुक्त रूप से उपयोग कर पूरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग व्यवस्था को ताकत देने का काम भी इस संगठन को करना है। श्री शाह ने कहा कि देश के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अपनी नेट एनपीए दर को कम कर 2.10% तक ले आए हैं और इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अंब्रेला संगठन को आने वाले 3 सालों में कठोर परिश्रम कर इसकी नींव डालनी चाहिए।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज शुरू हुई ये संस्था मात्र एक अंब्रेला संगठन नहीं है बल्कि हमारी सारी समस्याओं के समाधान का गेटवे है। उन्होंने कहा कि आम जनता के जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता कोई है तो केवल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनें, तब मोदी जी के मन में भी यह बात है कि आर्थिक विकास सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी हो। उन्होंने कहा कि अगर हमें यह कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना है तो हर गांव, शहर में युवाओं और स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है, इसके लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सिवा कोई रास्ता नहीं है। श्री शाह ने कहा कि यह अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का अंब्रेला संगठन छोटे बैंकों का सुरक्षा कवच है, जिससे हमारे डिपॉजिटर्स का हम पर विश्वास भी बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हमारे काम में भी बढ़ोतरी होगी।

ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर लगभग 5,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पंजीकृत हैं

10,000 के लक्ष्य की तुलना में 8000 से अधिक एफपीओ पंजीकृत हुए

1,101 एफपीओ को 246 करोड़ रुपये की गारंटीयुक्त क्रेडिट गारंटी जारी की गई, जिसमें 10.2 लाख से अधिक किसान शामिल हैं

नई दिल्ली। देश में उपभोक्ताओं को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए 8,000 पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में से लगभग 5 हजार को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। देश के किसी भी हिस्से में अपने खरीदारों तक पहुंचने के लिए ओएनडीसी पर एफपीओ को शामिल करना उत्पादकों को बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करने के केंद्र सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है। इस कदम का उद्देश्य इन किसान उत्पादक संगठनों की डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, बिजनेस-टू-बिजनेस और बिजनेस-टू-कंज्यूमर लेनदेन तक सीधी पहुंच को सशक्त बनाना है। 6,865 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ वर्ष 2020 में शुरू की गई "10,000 किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के सरकारी लक्ष्य की तुलना में 8,000 से अधिक एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं। इन एफपीओ में छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों का एकत्रित होना, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी आर्थिक ताकत और बाजार संपर्क बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है। एफपीओ किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेहतर प्रौद्योगिकी, ऋण, बेहतर इनपुट और अधिक बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं।

एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एफपीओ को संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 15 लाख प्रति एफपीओ की सीमा और पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं से प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण के साथ एफपीओ के प्रति किसान सदस्यों को 2,000 रुपये तक मैचिंग इक्विटी अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। अभी तक, 10.2 लाख से अधिक किसानों को कवर करते हुए 246 करोड़ रुपये की गारंटीकृत कवरेज के लिए 1,101 एफपीओ को क्रेडिट गारंटी जारी की गई है। 145.1 करोड़ रुपये का मैचिंग इक्विटी अनुदान पात्र 3,187 एफपीओ के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दिया गया है।

कृषि को आत्मनिर्भर कृषि में परिवर्तित करने के लिए एफपीओ का गठन और प्रचार पहला कदम है। यह पहल किफायती उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और एफपीओ के सदस्य की शुद्ध आय को बढ़ाती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ ग्रामीण युवाओं के लिए उनके गांवों में ही रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। किसानों की आय में उल्लेखनीय सुधार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम था।

एफपीओ को उपज समूहों में विकसित किया जाना है, जिसमें पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने और सदस्यों के लिए बाजार पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कृषि और बागवानी उपज की खेती या उत्पादन किया जाता है। विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए "एक जिला एक उत्पाद" क्लस्टर बनाए गए है। इसके अलावा कृषि मूल्य श्रृंखला संगठन एफपीओ का गठन कर रहे हैं और सदस्यों की उपज के लिए 60 प्रतिशत बाजार संपर्क की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- स्थायी आय-उन्मुख खेती के विकास और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और कृषि समुदायों के कल्याण के लिए 10,000 नए एफपीओ बनाने के लिए समग्र और व्यापक-आधारित सहायक इकोसिस्टम उपलब्ध कराना।
- कुशल, किफायती और सतत संसाधन उपयोग के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना और अपनी उपज के लिए बेहतर तरलता और बाजार जुड़ाव के माध्यम से अधिक आय प्राप्त करना और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से टिकाऊ बनना।
- एफपीओ के प्रबंधन, इनपुट, उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, बाजार लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज और प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि के सभी पहलुओं में सृजन के वर्ष से 5 साल तक नए एफपीओ को सहायता और समर्थन प्रदान करना।
- सरकार से समर्थन की अवधि के बाद आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि-उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए एफपीओ को प्रभावी क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- एफपीओ को या तो कंपनी अधिनियम के भाग 9ए के तहत या सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।

सरकार नुकसान की पूरी भरपाई करेगी - श्री यादव

इंदौर: गत दिनों मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में हुई आकस्मिक वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं , चना और सरसों की फसल को बहुत नुकसान हुआ। किसानों की इस पीड़ा पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में किसानों से कहा कि प्रदेश में ओला /पाला के कारण फसलों का नुकसान हुआ है। मैंने कलेक्टर सहित प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी किसान का किसी भी खेत में अगर एक रुपए का भी नुकसान हुआ है, तो सरकार पूरी भरपाई करेगी। किसी को भी कोई कष्ट नहीं आने देंगे। सरकार इस मामले में संवेदनशील है और सबके साथ खड़ी दिखाई देगी।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य विवरण संबंधित जानकारी

घोषणा फार्म चार (नियम – 8)

1.	प्रकाशन स्थल	:	**मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई - 8 / 77 शाहपुरा, भोपाल**
2.	प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	:	**गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई - 8 / 77 शाहपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	:	**गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई - 8 / 77 शाहपुरा, भोपाल
5.	सम्पादक का नाम	:	**गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित गणेश प्रसाद मांझी
6.	क्या भारतीय नागरिक हैं	:	**हाँ**
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो ।	:	यह समाचार पत्र मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं ।

मैं गणेश प्रसाद मांझी एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

दिनांक 16 मार्च 2024

सही / -
(गणेश प्रसाद मांझी)
प्रकाशक

कृषि श्रमिकों को अब मिलेंगे 7660 रु प्रति माह

इंदौर: मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से सभी औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों को 25 प्रतिशत अधिक मजदूरी मिलेगी। सभी औद्योगिक एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड-अनट्रेंड श्रमिकों का मेहनताना 1 अप्रैल 2024 से बढ़ जायेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 के बाद प्रदेश में पहली बार मजदूरों का मजदूरी का पुनरीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रयासों से श्रमिकों के कल्याण के लिये

की गई ठोस पहल है ।

कृषि श्रमिकों को देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर 1 अक्टूबर 2019 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को न्यूनतम वेतन में जोड़कर नई न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। नई न्यूनतम वेतन दरों के प्रभावशील होने पर कृषि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 7660 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। इसी प्रकार बीड़ी श्रमिकों एवं अगरबत्ती श्रमिकों के वेतन में भी देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। न्यूनतम वेतन की दरें किसी भी श्रमिक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी। वर्तमान वेतन की दरें संशोधित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएंगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दरें उसके समकक्ष नहीं हो जाती हैं।

पीएम ने सशक्त नारी – विकसित भारत कार्यक्रम में 1,000 दीदियों को सौंपे ड्रोन, 10 हजार करोड़ रुपये किए वितरित

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 मार्च को सशक्त नारी – विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लिया और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में नमो ड्रोन दीदियों के कृषि ड्रोन प्रदर्शन के साक्षी भी बने। देशभर में 10 अलग-अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियों ने भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान 1,000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपे। साथ ही प्रत्येक जिले में बैंकों के स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को लगभग 8,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को लगभग 2,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता निधि भी वितरित की। पीएम ने लाभार्थियों से बातचीत भी की।

लखपति दीदियां लिख रही सफलता के नए अध्याय

इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताया क्योंकि ड्रोन दीदियां और लखपति दीदियां सफलता के नए अध्याय लिख रही हैं। पीएम ने कहा कि ऐसी सफल महिला उद्यमियों के साथ बातचीत करना उन्हें देश के भविष्य को लेकर आश्वस्त करता है। उन्होंने नारी शक्ति के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की सराहना की। पीएम ने कहा कि इससे उन्हें 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की यात्रा शुरू करने का आत्मविश्वास मिला।

नारी शक्ति देश में प्रौद्योगिकी क्रांति का करेगी नेतृत्व

उन्होंने कहा कि आज कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी प्रभाव का नेतृत्व देश की महिलाएं कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी की आय, कौशल और मान्यता के माध्यम से सशक्तिकरण की भावना के बारे में विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि नारी शक्ति देश में प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करेगी। प्रधानमंत्री ने दूध और सब्जी उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, दवा वितरण आदि क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की, जिससे ड्रोन दीदियों के लिए नए रास्ते खुलेंगे।

स्वयं सहायता समूहों की आय में तीन गुना वृध्दि

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी की प्रभावशाली वृद्धि पर जोर देते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले दस वर्षों में, हमारी सरकार ने न केवल स्वयं सहायता समूहों का विस्तार किया है, बल्कि इनमें से 98% समूहों को बैंक खाते खोलने की सुविधा भी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि ऐसे समूहों को सहायता बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है और ऐसे समूहों के खातों में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे पर जोर देने से इन स्वयं सहायता समूहों की आय तीन गुना बढ़ गई है।

डिजिटल साक्षरता अभियान में 50 प्रतिशत महिला लाभार्थी

प्रधानमंत्री मोदी ने बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी और मत्स्य सखी की भूमिका और सेवाओं की सराहना की। पीएम ने कहा कि ये दीदियां देश के स्वास्थ्य से लेकर डिजिटल इंडिया तक के राष्ट्रीय अभियानों को नई गति दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने वालों में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं और 50 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी भी महिलाएं हैं।

प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन में बढ़-चढ़कर शामिल होने को कहा। उन्होंने कहा कि जहां भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य पहल करेंगे, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, डॉ मनसुख मंडाविया और श्री गिरिराज सिंह उपस्थित थे।

प्राकृतिक खेती बनी फायदे का सौदा

भोपाल : परम्परागत खेती अब बीते दौर की बात हो गई है। नया दौर उन्नत तकनीक और प्राकृतिक खेती का है। बालाघाट जिले के किसानों ने इस व्यवहारिक तथ्य को समझा और प्राकृतिक तरीके से खेती कर सर्वोत्तम किसान का सम्मान हासिल किया।

किसानों की प्रगतिशीलता और उद्यमशीलता को अवसर प्रदान करने के लिये हर जिले में आत्मा परियोजना संचालित की जा रही है। इस परियोजना में बालाघाट जिले में अत्यंत सराहनीय काम हुआ है। प्राकृतिक खेती अपनाकर यहां के पांच किसानों ने न केवल मुनाफा कमाया, बल्कि सर्वोत्तम किसान होने का सम्मान भी हासिल किया है। इन्हें प्राकृतिक खेती के प्रसार उन्नत कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करने एवं पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिये सम्मानित किया गया है।

बालाघाट जिले के कटंगी के किसान श्री रामेश्वर चौरीकर ने प्राकृतिक रूप से मशरूम की खेती करने के लिये रोचक तरीका अपनाया। इसके लिए रामेश्वर

ने 10 गुणा 10 के कमरे में दीवारों पर टाट और सतह पर रेत का उपयोग किया और सुबह-शाम स्प्रे कर इस कक्ष को वातानुकूलित बना लिया है। क्योंकि मशरूम की खेती के लिये तापमान 16 से 25 डिग्री सेल्सियस तक जरूरत के मुताबिक मेन्टेन करके रखना पड़ता है। 45 से 90 दिन में इसकी फसल आती है। मशरूम बाजार में 200 से 250 रूपये किलो तक बिकता है। पहली फसल बेचने पर ही रामेश्वर को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। मशरूम की खेती के इस नवाचारी तरीके के लिये रामेश्वर को 'जिले का सर्वोत्तम किसान पुरस्कार- मिला है। इसी तरह आगरवाडा (कटंगी) के श्री दीनदयाल को उन्नत कृषि तकनीकों से खेती- किसानी के लिये, थानेगाँव (वारासिवनी) के श्री नरेन्द्र सुलकिया को कृषि उद्यानिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये, बटरमारा (किरनापुर) के श्री हिरेन्द्र गुरवे को रेशम कीट पालन के लिये और चिचरंगपुर (बिरसा) के श्री जंगल सिंह को उन्नत नस्लों के पशुपालन से अतिरिक्त आय अर्जन के लिये जिलास्तरीय सर्वोत्तम किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अन्य 28 प्रगतिशील किसानों को उन्नत कृषि की विभिन्न श्रेणियों में ब्लॉकस्तरीय सर्वोत्तम किसान पुरस्कार दिया गया है। जिले के पांच सर्वोत्तम स्व-सहायता समूहों को कृषि में विशेष प्रदर्शन के लिये प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। बालाघाट जिले में प्राकृतिक (आर्गेनिक) खेती-किसानी यहां के किसानों के लिये बड़े फायदे का सौदा बन गई है। जिले के बडगाँव स्थित किसान विकास केन्द्र में किसानों को उन्नत व प्रगतिशील खेती के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट कराये जाते हैं। इन्हीं प्रशिक्षणों एवं एक्सपोजर विजिट्स में मिले नवाचारों से प्रेरित होकर किसानों ने यहां के किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोगी है। इससे किसानों के एक पंथ दो काज पूरे हो रहे हैं।

कृषकों को मण्डियों में सभी सुविधाएँ मिलना सुनिश्चित करें : कृषि मंत्री

मण्डी बोर्ड संचालक मण्डल की 142वीं बैठक आयोजित

भोपाल : कृषकों के लिये मण्डियाँ सुविधा-स्थली बनें। मण्डियों में कृषकों को सभी सुविधाएँ मिलना सुनिश्चित हो। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री-सह-अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री ऐदल सिंह कंषाना ने मंगलवार को मण्डी बोर्ड के संचालक मण्डल की 142वीं बैठक में उक्त निर्देश दिये। बैठक में मंत्री श्री कंषाना को मण्डी बोर्ड के एमडी श्री श्रीमन शुक्ल ने आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया।

कृषि मंत्री-सह-मण्डी बोर्ड अध्यक्ष श्री कंषाना ने कहा कि मण्डियों को सर्व-सुविधायुक्त बनाया जाये, जिससे मण्डियों में आने वाले कृषकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मण्डियों को आदर्श मण्डियों के रूप में विकसित किया जाये, जहाँ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, ठहरने के बेहतर प्रबंध हों और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो। मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि हम सभी को विभाग में ऐसे काम करना हैं, जिसे कृषक और अन्य लोग भी हमेशा याद रखें।

संचालक मण्डल की बैठक में पूर्व की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक में वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें आय शीर्ष में 300.52 करोड़ रुपये की सकल प्राप्ति एवं व्यय शीर्ष में 299.85 करोड़ रुपये का व्यय दर्शाया गया है। बैठक में उप सचिव श्री तरुण भटनागर, अपर संचालक कृषि श्री एस.सी. सिंगादिया, अपर आयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ श्री बी.एस. शुक्ला सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी! गेहूं खरीदी पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देगी सरकार

भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हैं। दरअसल सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं। कैबिनेट ने किसानों को गेहूं की खरीद पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने को मंजूरी दी है। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कैबिनेट ने 30,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी।

मध्यप्रदेश में फिलहाल 2,275 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है। अब सरकार 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदेगी। इसके अलावा, किसानों को खाद वितरण के लिये सहकारी संस्थाओं को नोडल एजेंसी बनाया गया। इसके लिए 850 करोड़ रुपए की निशुल्क शासकीय प्रत्यावृति स्वीकृत की गई है।

विश्व का सर्वश्रेष्ठ अनाज है श्रीअन्न-श्री पटेल

श्रीअन्न (मिलेट्स) प्रोत्साहन मेला एवं प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

भोपाल : पंचायात, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर में श्री अन्न प्रोत्साहन मेला में कहा कि इस समय लोगों को खिलाने के लिए मिलेट एक सस्ता और पौष्टिक विकल्प है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2017 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड फ़ूड फ़ेस्टिवल में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि विश्व को भुखमरी से बचाने के लिए हमें मोटे अनाजों की तरफ़ जाना होगा। प्रधानमंत्री ने 2018 में मोटे अनाज को पोषक–अनाज घोषित किया गया था। भारत के इन्हीं प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को 'इंटरनेशनल मिलेट इयर' घोषित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जी 20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों को प्रदान किए गए नाश्ते एवं भोजन में मिलेट्स को ही शामिल किया गया था।

मंत्री श्री पटेल ने मिलेट्स की उपयोगिता को समझाते हुए कहा कि मिलेट्स की खेती सर्वश्रेष्ठ है जो मानव और मिट्टी, दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देती है। इसके गुणों को हमारे पूर्वज बखूबी जानते थे। जनजातीय बंधुओं के ख़ान पान का यह आज भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्रीअन्न की पहचान दी गई है। श्रीअन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। श्रीअन्न यानि कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार, श्रीअन्न यानि केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार, श्रीअन्न यानि क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिसमें वॉटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए यह एक पसंदीदा फसल बन जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी जैसे श्री अन्न का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मिलेट भारत में सदियों से जीवनशैली का हिस्सा रहा है। जहां विश्व में एक तरफ़ खाद्य सुरक्षा की समस्या है तो वहीं दूसरी तरफ़ फूड हैबिट्स से जुड़ी बीमारियां,बीपी,डायबिटीज एक बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। उन्होंने बताया कि श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं, ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। पहले मोटे अनाज को ग़रीबों का अनाज कहकर मजाक उड़ाया जाता था लेकिन आज पूरी दुनिया ने माना है कि श्रीअन्न दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अन्न है।

उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच मोटे अनाज के प्रचार और जागरूकता, उनकी मूल्य श्रृंखला का विकास, मिलेट के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलू, बाजार संपर्क, अनुसंधान और विकास आदि जैसे श्रीअन्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पीजी कॉलेज नरसिंहपुर में श्रीअन्न (मिलेट्स) प्रोत्साहन मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम विभाग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया गया।

इंदौर में समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन हेतु जिला उपार्जन समिति गठित

इंदौर: रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन हेतु उपार्जन के संपूर्ण कार्य, पर्यवेक्षण, उपार्जन की समस्त प्रक्रिया, स्कंध की गुणवत्ता, भण्डारण, निरीक्षण, उपार्जन नीति अंतर्गत आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करने हेतु जिला उपार्जन समिति गठित की गई है। जिला कलेक्टर इस जिला उपार्जन समिति के अध्यक्ष रहेंगे। इस समिति में जिला लीड बैंक अधिकारी, उप संचालक कृषि, उपायुक्त/सहायक आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला सूचना अधिकारी, सीईओ आईपीसी बैंक, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, शाखा प्रबंधक वेयर हाउसिंग, अधीक्षक भू-अभिलेख और सचिव, कृषि उपज मंडी सदस्य होंगे। जिला आपूर्ति नियंत्रक इस समिति के सदस्य सचिव रहेंगे।

गठित समिति शासन द्वारा जारी रबी विपणन वर्ष 2024-25 की उपार्जन नीति में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सौंपे गये समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगी। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन हेतु उपार्जन की संपूर्ण कार्यवाही हेतु अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश कृषि, खाद्य और डेयरी प्रोसेसिंग में निवेश के लिए देश का सर्वाधिक अनुकूल राज्य

भोपाल : मध्यप्रदेश, देश का सबसे अच्छा फूड बास्केट है। कृषि खाद्य तथा डेयरी प्रोसेसिंग उद्योगों में निवेश के लिए आज की स्थिति में मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक अनुकूल राज्य है। उज्जैन में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव-2024 के प्रथम दिवस सेमिनार में शामिल उद्योगपतियों तथा एंटरप्रेन्योर्स ने मध्यप्रदेश में एग्रीकल्चर, फूड तथा डेयरी प्रोसेसिंग के विकास एवं निवेश की अपार संभावना पर चर्चा की और इस दिशा में मध्यप्रदेश शासन की सकारात्मक उद्योग नीति की सराहना की। सेमिनार के द्वितीय सत्र में प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एस.एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव पशुपालन तथा डेयरी श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव उद्यानिकी तथा फूड प्रोसेसिंग श्री सुखबीर सिंह, सीनियर मैनेजर पेप्सीको श्री संदीप समदार, आईटीसी के वाइस प्रेसिडेंट श्री सचिन शर्मा, ट्रॉपी लाइट फूड्स के सीईओ श्री पुनीत डावर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मदर डेयरी श्री जेटी चारी शामिल थे।

सेमिनार में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मिश्रा ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने निवेशकों से कहा कि बिना

(पृष्ठ 1 का शेष)

किसी परेशानी के उनको सभी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। टमाटर, सोयाबीन, गेहूँ, मक्का, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। देश की 27% जैविक खेती मध्यप्रदेश में होती है। प्रमुख सचिव श्री बामरा ने उद्योगपतियों को बताया कि मध्यप्रदेश विविध कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों में देश में अग्रणी स्थान रखता है। साथ ही मध्यप्रदेश की उद्योग फ्रेंडली नीति से डेरी खाद्य तथा कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में नवीन आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में 25 लाख हेक्टेयर भूमि में उद्यानिकी उत्पाद लिए जा रहे हैं। उद्यानिकी उत्पादों के समग्र रूप से उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मध्यप्रदेश में फूल फल तथा एरोमेटिक फसलों के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। खाद्य डेरी प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए सकारात्मक उद्योग नीति बनाई गई है। प्रदेश में प्लांट तथा मशीनरी पर 40% तक सब्सिडी दी जा रही है। फूड पार्क के मामले में प्रोजेक्ट कॉस्ट की 15% राशि सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। कृषि खाद्य एवं डेयरी की सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के संबंध में अतिरिक्त रूप से शासन द्वारा इंसेंटिव प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अतिरिक्त तथा निर्यात करने वाली इकाइयों को एडिशनल 12% इंसेंटिव दिया जा रहा है।

सेमिनार में बताया कि मध्यप्रदेश में कृषि तथा खाद्य प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। मध्यप्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर में कृषि सिंचाई की सुविधा है। प्रदेश में बेहतर वेयरहाउसिंग कैपेसिटी है, 13 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्षमता के कोल्ड स्टोरेज है। मध्यप्रदेश में 15 फूड क्लस्टर बनाए गए हैं। मध्यप्रदेश में प्रतिदिन साढ़े 5 लाख किलोग्राम दुग्ध उत्पादन होता है, जो सरप्लस है। दुग्ध उत्पादन में 9 से 10% ग्रोथ की पूर्ण संभावनाएं हैं।

सेमिनार में वाइस प्रेसिडेंट तथा एग्री एंड डेरी ऑपरेशनल आईटीसी श्री सचिन शर्मा ने वर्तमान परिदृश्य की चुनौतियां मध्यप्रदेश में निवेश के बेहतर अवसर, मध्यप्रदेश की बेहतर उद्योग फ्रेंडली पॉलिसी तथा सहयोगी शासकीय मशीनरी की जानकारी दी। उन्होंने ई प्लेटफॉर्म क्लाइमेट चेंज पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि हम मध्यप्रदेश में 1000 करोड़ रूपए का निवेश कर फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में कृषि आधारित उद्योग इकाइयों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। औद्योगिक पॉलिसी उद्योगपतियों के लिए अत्यंत सहयोगी है। मध्यप्रदेश निवेश के लिए एक आदर्श राज्य है।

सेमिनार में मदर डेयरी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जेटी चारी ट्रॉपी लाइट फूड्स के सीईओ श्री पुनीत डावर पेप्सिको के सीनियर मैनेजर श्री संदीप समदार ने भी अपनी कंपनियों के औद्योगिक उत्पादों तथा मध्यप्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण की बात कही। उन्होंने बताया कि वे उज्जैन की विक्रम उद्योग पुरी में भी औद्योगिक इकाई की स्थापना कर रहे हैं

सेमिनार में युवा उद्योगपतियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। प्रमुख सचिव श्री सुखबीर सिंह तथा श्री गुलशन बामरा द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध कराई गई।

डेटाबेस से सहकारिता की हर एक जानकारी....

श्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में तीन चरणों में काम हुआ है। पहले चरण में, तीन क्षेत्रों यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति, डेयरी और मत्स्यिकी की लगभग 2.64 लाख समितियों की मैपिंग पूरी की गई। दूसरे चरण में विभिन्न राष्ट्रीय संघों, राज्य संघों, राज्य् सहकारी बैंक (StCB), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB), शहरी सहकारी बैंक (UCB), राज्यट सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDB), प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB), सहकारी चीनी मिलों, जिला यूनियनों और बहुराज्य सहकारी समितियों (MSCS) के आंकड़े एकत्रित/मैप किए गए। तीसरे चरण में अन्य बाकी क्षेत्रों में सभी 8 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों के डेटा की मैपिंग की गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमें पता चला कि देश में 8 लाख से अधिक समितिया पंजीकृत हैं औऱ 30 करोड़ से अधिक नागरिक इनसे जुड़े हैं। श्री शाह ने कहा कि डेटाबेस में पैक्स से एपैक्स, गांव से शहर, मंडी से ग्लोबल मार्केट औऱ स्टेट से अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस तक जोड़ने की पूरी संभावना मौजूद है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा Whole of Government Approach के साथ शुरू किए गए सहकारिता के विस्तार के अभियान में यह डेटाबेस रास्ता प्रशस्त करने का काम करेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में कंप्यूटराइजेशन से जुड़े कई इनिशिएटिव लिए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पैक्से से लेकर ऐपैक्स तक पूरी सहकारिकता को कंप्यूटराइज कर इसकी ताकत बढ़ाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि यह डेटाबेस भारत की पूरी सहकारिता गतिविधियों की जन्मकुंडली है। श्री शाह ने कहा कि यह राष्ट्रीय डेटाबेस अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाया गया एक डायनेमिक वेब आधारित प्लेटफार्म है और इसकी मदद से देशभर की पंजीकृत सहकारी समितियों की सारी जानकारी एक क्लिक से उपलब्ध होगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि ये सहकारिता डेटाबेस, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और स्टेकहोल्डर के लिए अमूल्य संसाधन का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस डेटाबेस के आंकड़ों की प्रामाणिकता और उन्हें अपडेट करने के लिए पूरी साइंटिफिक व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि इस डेटाबेस पर सत्यापित डाटा ही नियमित रूप से अपलोड हो। श्री शाह ने कहा कि 1975 के बाद देश में सहकारिता आंदोलन की गति बहुत कम होती गई क्योंकि हमारे यहां ज्योग्राफिकली असंतुलित विकास हुआ। इसके साथ-साथ अक्रॉस सेक्टर असंतुलन भी बढ़ा, अक्रॉस कम्युनिटी असंतुलन भी बढ़ा और फंक्शनल असंतुलन भी बढ़ा, आज इन चारों समस्याओं का समाधान टूल्स के साथ इस डेटाबेस में डाला गया है। श्री शाह ने कहा कि आज हज़ारों लोगों, संघों और राज्यों ने मिलकर एक भागीरथ काम को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि आज एक नींव डाली गई है और आने वाले वर्षों में इस नींव पर अगले सवा सौ साल तक चलने वाली एक मजबूत सहकारिता की इमारत खड़ी होगी।

मछुआ कल्याण की योजनाओं एवं गतिविधियों को बढ़ाया जायेगा : मंत्री श्री पंवार

भोपाल : मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पवार की अध्यक्षता में मत्स्य महासंघ की कामकाज समिति की 109वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2024-25 के बजट का अनुमोदन किया गया।

मंत्री श्री पवार ने महासंघ कामकाज इंदिरा सागर एवं वरगी इकाईयों की समीक्षा करते हुए कहा कि महासंघ के जलाशयों की उत्पादन क्षमता को 50 किलो प्रति हेक्टेयर लाया जाये। वर्तमान में जलाशयों का औसत उत्पादन 35 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसे बढ़ाने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। महासंघ की वर्तमान आय में यथोचित वृद्धि सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मछुआ कल्याण की योजनाओं एवं विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाया जायेगा। मंत्री श्री पवार ने कहा कि भदभदा परिक्षेत्र में एक उपयुक्त विश्राम गृह का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि महासंघ द्वारा शासन को दी जाने वाली छ: रूपये किलो की रायल्टी को भी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करे। मंत्री श्री पवार ने कहा कि इंदिरा सागर जलाशय जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है उसकी निविदा यथा शीघ्र आमंत्रित कर सक्षम निविदाकारों से संपर्क कर उन्हें प्रेरित करे, इससे अधिक सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार महासंघ के अन्य जलाशयों जिनकी निविदा नहीं हुई है, उनकी निविदा शीघ्र आमंत्रित करने के भी निर्देश दिये। इससे मछली उत्पादन में वृद्धि हो। बैठक में अंकेक्षण आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा कर अनुमोदन किया गया। उन्होंने कहा कि मत्स्य उत्पादन के लक्ष्यों को तत्परता से पूर्ण करे। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए। नियमानुसार प्रगति की जानकारी प्राप्त कर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जाये। बैठक में प्रबंध संचालक श्री नवनीत मोहन कोठारी, संचालक श्री भरत सिंह मत्स्य सहित सदस्य उपस्थित थे।

बी-पैक्स के मॉडल बायलॉज एवं मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 पर जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधकों एवं पैक्स प्रबंधकों हेतु प्रशिक्षण आयोजित

भोपाल। प्रमुख सचिव, सहकारिता मध्यप्रदेश शासन एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश के निर्देश के परिपालन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ में मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 एवं बी-पैक्स के मॉडल बायलॉज के प्रावधान व उनके समुचित क्रियान्वयन हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 26/02/2024 से 27/02/2024, दिनांक 28/02/24 से 29/02/24 तक जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के समिति प्रबंधकों को दिनांक 11/03/24 से 12/03/24, दिनांक 13/03/24 से 14/03/24 तक कुल 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में सफलतापूर्वक आयोजित किये गयें। जिसमें कुल 74 जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक एवं पैक्स प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण पर जानकारी देते हुए श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या0 भोपाल द्वारा बताया गया कि सहकार से समृद्धि की दिशा में सहकारिता विभाग म.प्र. के सहकारी क्षेत्र से जुड़े जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक एवं पैक्स प्रबंधक को निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारिता पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। जिसमें श्री अरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा बी-पैक्स के नवीन बायलाज अनुसार बी-पैक्स की प्रमुख गतिविधियां एवं क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश, श्री अभय गोखले, से.नि. प्रबंधक, अपेक्स बैंक भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी नीति 2023 क्या है, इसकी आवश्यकता, विजन, मिशन एवं उददेश्य व सहकारी नीति के प्रमुख प्रावधान, विषय विशेषज्ञ श्री श्रीकुमार जोशी, सेवा निवृत्त, संयुक्त आयुक्त सहकारिता बी-पैक्स की उपविधि, सहकारी अधिनियम व नियम के प्रावधान सहकारी नीति के संदर्भ में, एवं मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 क्रियान्वयन हेतु, एक्शन प्लान का क्रियान्वयन, सहकारिता के विशिष्ठ सेक्टर जैसे- कृषि साख, स्वॉट एनालिसिस, बीज उत्पादन, डेयरी, मत्स्य एवं लघु वनोपज एवं किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.),

श्री अरविंद सिंह सेंगर, सेवा निवृत्त, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा बी-पैक्स नवीन बायलॉज की आवश्यकता व उद्देश्य एवं सेवाऐं, श्री अविनाश सिंह, से.नि.व.सहकारी निरीक्षक द्वारा बी पैक्स के नवीन बॉयलाज को प्रभावशील किया जाना, श्री अशोक शर्मा से.नि. क्वालिटी कंट्रोलर, म.प्र. वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल, द्वारा वृहद भण्डारण योजना को बी-पैक्स में लागू करना, श्री अतुल श्रीवास्तव, साईबर विशेषज्ञ, राज्य साईबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा साईबर अपराध पर, श्रीमती मीना रघुवंशी एवं श्रीमती रश्मि गोलिया मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा तनाव एवं समय प्रबंधन विषय पर, श्री जी.पी. मांझी प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल एवं श्री संतोष येडे राज्य समन्वयक द्वारा श्री सेवड़ी सेवा सहकारी मण्डली सूरत गुजरात मल्टी सर्विस सेंटर (PACS as MSC) के रूप में कार्य कर रहें गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम सत्र में प्रबंध संचालक एवं महाप्रबंधक राज्य संघ द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी नीति 2023 के प्रमुख प्रावधान पर प्रतिभागियों से खुली चर्चा की गई एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का फीडबैक लिया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्री जी.पी. मांझी प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल एवं श्री अरूण कुमार जोशी,से.नि.प्राचार्य द्वारा किया गया। श्री संतोष येडे राज्य समन्वयक, श्री धनराज सैंदांणे, श्री प्रवीण कुशवाहा, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री ज्ञानू सिंह, श्री विनोद कुशवाह, मो.शाहिद खांन का विशेष सहयोग रहा।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम सम्पन्न

नौगावा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 5 मार्च 2024 से 7 मार्च 2024 तक सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव में आयोजित किया गया| कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनूप तिवारी जी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात केंद्र के प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित द्वारा अतिथियों एवं व्याख्याताओं का फूल मालाओं से स्वागत वंदन व अभिनंदन किया| उद्यानिकी विभाग से पधारे श्री मुकेश कुशवाहा द्वारा उद्यानकी संबंधी एवं सरकारी योजनाओं की महत्वरपूर्ण जानकारी प्रदान की गई । मत्स्य विभाग, छतरपुर से पधारे मत्स्य निरीक्षक श्री एस. के. साहू द्वारा मत्स्यपालन व अच्छी प्रजाति की मछली उत्पादन से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव के प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित द्वारा सहकारिता

एवं साईबर अपराध से संबंधित जानकारी विस्तार से बताई गई। द्वितीय दिवस पर कृषि विभाग, नौगांव से पधारे श्री सूरजभान पटेल, एसडीओ द्वारा कृषि संबंधी जानकारी दी गई। एसबीआई आरसेटी नौगांव से आए फैकेल्टी श्री राजाराम कुशवाहा द्वारा उद्यमिता विकास संबंधी जानकारी दी गई।

तृतीय दिवस पर जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक, श्री हृदेश कुमार राय द्वारा सहकारिता का अर्थ एवं समिति के उद्देश्य व संचालक मंडलों के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित जानकारी दी गई,। कु.मेघा, HDERF होमगार्ड ऑफिस, छतरपुर द्वारा आपदा से निपटने संबंधी जानकारी दी गई। सभी संचालकों को कमलापति मछुआ मत्स्य सहकारी समिति, धुवेला में अध्य यन भ्रमण कराया गया। समिति के अध्यक्ष श्री रामकुमार रैकवार द्वारा विभिन्न प्रकार की मछलियों की प्रजाति और मछली पालन से संबंधित विस्तायरपूर्वक जानकारी प्रदान की गई, इसके पश्चात धुबेला संग्रहालय, रानी महल सहित कई पर्यटनों के दर्शन किए।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर एसबीआई आरसेटी के निदेशक श्री प्रकाश गरेहटे व केंद्र के प्राचार्य द्वारा सभी संचालकों को प्रशिक्षण कीट वितरित की गई। सभी संचालकों ने सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

महिला सहकारी समितियों के कुशल संचालन के लिए नेतृत्व विकास का प्रशिक्षण आवश्यक : श्री ऋतुराज रंजन

जबलपुर। महिला सहकारी समितियों के कुशल और सफल संचालन के लिए आज इन समितियों के संचालकों के लिए नेतृत्व विकास पर प्रशिक्षण आवश्यक है क्यों कि जब तक संचालकों को सहकारी अधिनियम, उपनियमों और अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी नहीं होगी तब तक समितियों का संचालन दक्षतापूर्वक नहीं हो पायेगा, ये विचार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के प्रबंध संचालक श्री आर. आर. रंजन ने संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र कंटगा, जबलपुर में आयोजित त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में व्यक्त किये। यह प्रशिक्षण शिविर महिला सहकारी समितियों के संचालकों के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रुप में संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री पी. के. सिद्धार्थ ने शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण को महिला सहकारिता के सुचारू संचालन के लिए उपयोगी बताया। विशेष अतिथि के रुप में सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक श्री अशोक सिंघै ने सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण की गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य सहकारी संघ और जिला सहकारी संघ की सराहना की। अतिथि वक्ताओं के रुप में एम. पी. प्रिटिंग प्रेस औधोगिक सहकारी समिति के प्रबंधक श्री के. के. तिवारी, सहकारी अंकेक्षक श्री पी के बैनर्जी, जिला संघ के प्रबंधक श्री राकेश वाजपेयी ने भी विचार व्यक्त किये। विषय विशेषज्ञ के रुप में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के पूर्व प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक, श्री शशिकांत चतुर्वेदी के साथ प्राचार्य श्री व्ही के बर्वे ने सहकारी प्रबंध, सहकारी विधान और वित्तीय लेखाकंन पर प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में केन्द्र के प्राचार्य श्री व्ही के बर्वे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए स्वागत भाषण दिया। इस त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षार्थियो को प्रियदर्शिनी स्व सुविधा केन्द्र सिविक सेंटर का अध्ययन भ्रमण कराया गया। इस अध्ययन भ्रमण के दौरान प्राचार्य श्री वी.के.वर्बे के मार्गदर्शन में प्रियदर्शिनी स्व सुविधा

केन्द्र के प्रबंधक श्री एम.के.बहरे ने स्व सुविधा केन्द्र की समस्त जानकारियों से प्रशिक्षार्थियों को अवगत कराया। समापन अवसर पर प्रशिक्षार्थियो को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। प्रशिक्षण के सफल आयोजन में प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षक श्री पीयूष रॉय, श्री जय दुबे, श्री अखिलेश उपाध्याय एवं लेखापाल श्री एन पी दुबे का सहयोग सराहनीय रहा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) तथा कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। डॉ. यू.एस. गौतम, उप-महानिदेशक (कृषि विस्तार), भाकृअनुप तथा श्री सुबोध मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट, सीएससी-एसपीवी ने इस एएमयू पर हस्ताक्षर किए।

डॉ. गौतम ने कहा सीएससी सेंटर के माध्यम से जिला स्तर पर केवीके से प्राप्त सूचना को पंचायत स्तर तक किसानों को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सीएससी के 5 लाख से ज्यादा सर्विस सेंटर है, जिसके माध्यम से टेली पशु चिकित्सा जैसे प्रोग्राम के साथ-साथ प्लांट प्रोटेक्सन, हॉर्टिकल्चर तथा होम साइंस एवं मेकेनाइजेशन जैसे क्षेत्र में टेलीकम्यूनिकेशन प्रोग्राम शुरू करने का परिषद का लक्ष्य है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारा सम्पर्क बनें। उप-महानिदेशक ने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोग तकनीकी फायदा ले सकेंगे और इसका कृषि में उपयोग कर अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। सीएसी सेंटर के माध्यम से कृषि से संबधित सूचना, जैसे- खेत में कब पानी डालना है तथा कौन से खेत में कीटनाशक का छिड़काव करना है ये सभी इन्फॉर्मेशन उचित समय पर किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा, जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई जा सके।

उप-महानिदेशक ने बताया कि अभी 5 लाख सीएससी सेंटर है, यदि प्रत्येक केन्द्र से सौ लोगों को भी जोड़ा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। भाकृअनुप का प्लान है कि देश के 11 करोड़ किसानों को केवीके से, किसान सारथी से तथा सीएससी से जोड़ा जाए जिससे केवीके तथा आत्मा के कार्य को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर भाकृअनुप के सहायक महानिदेशक, निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।